Statement

Statement of Statewise Cast related incidents for the year 1996 and first quarter of 1997

S. No.	Name of the State	Number of Incidents (Ist Quarter)		Number of death (Ist Quarter)		Number of Persons injured (Ist Quarter)	
		1996	1997	1996	1997	1996	1997
1.	Andhra Pradesh	10	4	4	—	27	21
2.	Bihar	132	39	72	21	177	15
3.	Delhi	1	—	—	—	7	—
4.	Gujarat	13	4	4	2	36	8
5.	Haryana	3	—	2	—	28	—
6.	Himachal Pradesh	1	—	—	—	1	—
7.	Jammu & Kashmir	1	—	—	—	—	—
8.	Karnataka	17	2	2	1	84	7
9.	Kerala	2	—	1	—	—	—
10.	Madhya Pradesh	13	1	5	1	18	—
11.	Maharashtra	61	9	4	2	51	11
12.	Orissa	8	3	2	—	21	14
13.	Punjab	2	—	—	—	20	—
14.	Rajasthan	33	2	8	—	56	2
15.	Tamilnadu	282	41	57	4	744	112
16.	Uttar Pradesh	93	43	43	36	112	65
17.	West Bengal	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	672	148	204	67	1382	255

Structural Reforms for the Police

3406. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for not taking steps to reform the Indian police structurally as it still has to work under the conditions laid down by a colonial enactment of 1891;

(b) whether Government consider that the police have to change their ethos from enforcement to enablement and function as social workers in uniform; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) Police is a State subject as per the Seventh Schedule of the Constitution of India. It is primarily for the State Governments to take necessary steps to restructure their police force and reform its functioning. After Independence, some State Governments have enacted their own Police Acts.

Review of TADA Cases

3407. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI MOHD. MASUD KHAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the steps taken and progress made in the review of cases of TADA detenues

in different States so far;

(b) the number of cases reviewed and persons released and the number who still remain in detention without review so far; and

(c) the details of persons who remained in detention for over a year before review and release, and these still under detention?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) As per the direction of the Supreme Court the review committees for the Central Government as well as the States/UTs Governments have been constituted. As a result of these reivews and concerted efforts made by the Central Government as many as 11899 TADA cases have been reviewed so far as per the reports last received which resulted in dropping of TADA provisions against as many as 28502 persons. As per reports last received 1599 persons are still in detention in various states in the country.

दिल्ली में हत्याएं

3408. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पिछले एक वर्ष में कितनी हत्याएं हुईं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में हुई हत्याओं के मुकाबले यह संख्या कितनी कम या अधिक है;

(ग) इनमें से कितनी हत्याएं घरेलू नौकरों के द्वारा की गईं; और

(घ) हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मो० मकबूल डार): (क) से (घ) गत वर्ष तथा इसके पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूचित की गई हत्याओं की संख्या इस प्रकार थी:—

वर्ष	मामले	मारे गए व्यक्ति	कथित रूप से नौकरों द्वारा मारे गए व्यक्ति
1991	503	555	4
1992	529	566	4
1993	493	527	14
1994	491	517	2
1995	525	575	11
1996	518	565	4

हत्या सहित अपराध पर नियंत्रण/काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

I) गश्त की मौजूदा बीट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्ञात बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई पुरानी अपराधिक पृष्ठभूमि न होने के कारण पुलिस के जाल से प्रायः बच निकलने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

II) खतरनाक अपराधियों के आवागमन के बारे में आसूचना लगातार तैयार की जाती है और इन अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापे मारे जाते हैं। खासतौर से अंधेरी रातों में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि आपराधिक गिरोहों में ऐसी रातों में ही सक्रिय होने की प्रवृत्ति होती है।

III) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों तथा उनके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का सत्यापन किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है।

IV) अपने नौकरों का सत्यापन कराने के लिए नागरिकों को सक्रिय करने के लिए नौकरों का पूर्ववृत्त सत्यापन अभियान चलाया गया।

V) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में "पड़ोसी निगरानी योजना" की गई है। बीट अधिकारी समय-समय पर वृद्ध नागरिकों के पास जाते रहते हैं।

VI) जघन्य अपराधों का पता लगाने के लिए अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

VII) गंभीर अपराधों की जांच-पड़ताल प्रभावी